पहले राउंड की काउंसलिंग की पात्रता को लेकर दायर याचिका खारिज

■ हाईकोर्ट ने पीसीपीएनडीटी के तहत छह माह के अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित पहली काउंसलिंग में स्थानीय चिकित्सक को आरक्षण देने को सही माना है

■ अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है और यह संविधान के प्रावधानों के भी विपरीत नहीं है

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीसीपीएनडीटी के तहत छह माह के अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित पहली काउंसलिंग में स्थानीय चिकित्सक को आरक्षण देने को सही माना है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अनूप अग्रवाल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है और यह संविधान के प्रावधानों के भी विपरीत नहीं है।

याचिका में बताया कि पीसीपीएनडीटी के तहत छह माह का अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स कराने के लिए गत 22 अप्रैल को नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड ने विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए है। जिसमें प्रावधान किया गया कि पहले राउंड में प्रदेश की मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले चिकित्सकों और सेवारत डॉक्टरों को ही शामिल किया जाएगा। वहीं यदि इसके बाद सीटें रिक्त रही तो दूसरे और बाद में राउंड में प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस करने वालों को मौका दिया जाएगा। इसके चुनौती देते हुए कहा गया कि नेशनल मेडिकल कमीशन देश में कहीं से भी एमबीबीएस करने वाले चिकित्सकों को योग्यता के आधार पर एक समान मानता है। ऐसे में इस कोर्स में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता के साथ स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पीसीपीएनडीटी नियम, 2014 के तहत नीट पीजी के अंकों के आधार पर इस कोर्स में प्रवेश का प्रावधान है। पाठ्यक्रम की सीटों पर सौ फीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि पहले राउंड में प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी भी पात्र हैं। दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी प्रदेश में सेवारत हैं या यहां की कॉलेज से एमबीबीएस हैं, उन्हें पात्र माना गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भी संस्थागत आरक्षण में पचास फीसदी व नियोजित कर्मचारियों के लिए पचास फीसदी आरक्षण को सही माना है। वहीं कोर्स में प्रदेश के लिए दूसरे राउंड के लिए अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी पात्र माना गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।

पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत पर सुनवाई जारी

जयपुर। ईडी मामलों की विशेष अदालत में मंगलवार को जल जीवन मिशन प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से अपनी बहस पूरी कर ली गई है। वहीं ईडी जमानत अर्जी पर 28 मई को बहस करेगी।

महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने अदालत को बताया कि एसीबी की एफआईआर और मामले में पेश आरोप पत्र में उसका नाम नहीं है। ईडी ने मार्च, 2024 में उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद करीब एक साल तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और गत दिनों उसे अचानक बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में अन्य आरोपियों की पूर्व में ही जमानत हो चुकी है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मंगलवार को विधानसभा में पशुपालन एवं डेयरी, गोपालन व देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने शिष्टाचार मुलाकात की। कुमावत ने देवनानी का दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनन्दन किया। कुमावत ने देवनानी को विभाग की पुस्तिका भेंट की।

नौतपा में भीषण गर्मी से बचाने के लिए बड़ी चौपड़ पर पानी की फुहार फेंक कर लोगों को कुछ राहत देने का प्रयास किया गया।

पशुपालकों के खाते में 88.43 करोड़ की अनुदान राशि डीबीटी

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के दुग्ध उत्पादकों को 88.43 करोड़ की अनुदान राशि का भुगतान किया है। यह राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दी गई है। राज्य सरकार की ओर से सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों पर दूध देने वालों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान किया जाता है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के करीब साढे चार लाख पशुपालक किसानों के बैंक खाते में यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित की गई है।

'आवास भवन' को ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा मिली 5 स्टार रेटिंग

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीनस्थ प्रतिष्ठित ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा मुख्यालय भवन आवास भवन को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है।

जयपुर। राजस्थान आवासन मण्डल ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में मिसाल कायम की है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीनस्थ प्रतिष्ठित ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा मुख्यालय भवन आवास भवन को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है।

यह उपलब्धि भवन की ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और सतत विकास के प्रति मण्डल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस उपलब्धि को राजस्थान में सरकारी भवनों के लिए एक प्रेरणास्त्रोत के रूप में देखा जा सकता है। ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक भवन के डिजाइन और निर्माण के दौरान ऊर्जा दक्षता का मूल्यांकन करता है। यह ऊर्जा उपयोग का माप है, जो प्रति वर्ग मीटर या प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को दर्शाता है। का उपयोग करके ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए बेहतर इंसुलेशन, अधिक कुशल उपकरण या नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा दक्षता को मापने व सुधारने में किया जाता है।

इस अवसर पर आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने कहा की यह सम्मान हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है, और यह हमारी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। हम ऊर्जा दक्षता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रयासरत है कि हमारी आवासीय योजनाओं में भी हम 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करें। राज्य सरकार की मंशानुसार राजस्थान आवासन मण्डल आगे भी ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और सतत शहरी विकास के लिए कार्य करता रहेगा।

स्वर्ण जयंती पार्क, मजार डेम एवं किशन बाग को विकसित करने के लिए उच्चस्तरीय बैठक

जयपुर। राज्य बजट घोषणा की स्वीकृति के तहत विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयंती पार्क, मजार डेम एवं किशन बाग के धोरों को भारतीय सेना के सहयोग से मॉडल स्वरूप में विकसित किए जाने को लेकर आज एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर गहन चर्चा की गई।

यह बैठक उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ साउथ वेस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त आनंदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में क्षेत्र के समग्र विकास, सौंदर्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सैन्य सहयोग के माध्यम से क्षेत्र को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों को स्वच्छ, हरित एवं शैक्षिणक मनोरंजन से युक्त विकसित करना है, जिससे स्थानीय नागरिकों, युवाओं, बच्चों और पर्यटकों को एक समृद्ध एवं प्रेरणादायक वातावरण मिल सके।

इस पहल से न केवल क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी बल्कि सेना और नागरिक प्रशासन के समन्वित प्रयासों से एक आदर्श मॉडल भी प्रस्तुत होगा, जो राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगा।

महाराणा प्रताप जयंती पर कार्यक्रम "शौर्य गाथा के रंग" आयोजित होगा

■ बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे मुख्य अतिथि

■ कार्यक्रम संयोजक प्रेम सिंह बनवासा ने बताया, महाराणा प्रताप के जीवन पर फिल्म भी दिखाई जाएगी

जयपुर। स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप की जयंती पर महाराणा प्रताप फाउंडेशन बुधवार को भव्य आयोजन शौर्य गाथा के रंग करने जा रहा है। बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। कार्यक्रम संयोजक प्रेम सिंह बनवासा ने यह जानकारी दी।

मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में संयोजक प्रेम सिंह बनवासा ने बताया कि हमें यह बात साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि महाराणा प्रताप फाउंडेशन विगत कई वर्षों से भारत भूमि के महानतम योद्धा, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक महाराणा प्रताप की गौरवगाथा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है। फाउंडेशन का उद्देश्य केवल इतिहास का स्मरण करना नहीं, बल्कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति, आत्मबलिदान और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत करना भी है। बनवासा ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन न केवल वीरता का प्रतीक है, बल्कि उनके द्वारा दर्शाया गया स्वराज्य का संकल्प, कठिन परिस्थितियों में स्वाभिमान से समझौता न करने का अद्वितीय साहस और गौरवपूर्ण जीवन मूल्यों का अनुपम उदाहरण आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है।

संयोजक प्रेम सिंह बनवासा ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा नियमित रूप से शौर्य-गाथा संगोष्ठियां, शैक्षिक संगठनों में व्याख्यान, बाल एवं युवा वर्ग के लिए निबंध प्रतियोगिताएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाटक एवं प्रदर्शनी के माध्यम से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जीवनगाथा का प्रसार किया जाता है। उन्होंने बताया कि शौर्य गाथा के रंग कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप के जीवन पर फिल्म दिखाई जाएगी। कवि महाराणा प्रताप की वीरगाथा को अपनी कविताओं के माध्यम से बताएंगे। संयोजक बनवासा ने बताया कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सहकारिता मंत्री गौतम दक, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य, जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।

शिक्षा विभाग तीन सप्ताह में बनाए रिवीजन कमेटी : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस से जुडे विवाद को लेकर डिवीजनल कमेटी के आदेश की रिवीजन सुनने के लिए पिछले 9 साल से रिवीजन कमेटी नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने शिक्षा विभाग को तीन सप्ताह में रिवीजन कमेटी बनाकर एक जुलाई को पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश की पालना नहीं हुई तो दोषी अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल वीसी के जरिए उपस्थित हुए। शिक्षा विभाग की ओर से एएजी बीएस छाबा ने कहा कि फीस एक्ट के तहत रिवीजन कमेटी बनाने में छह सप्ताह का समय लगेगा। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि एक ओर तो शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र पेश कर कहा था कि कि फीस विवाद के लंबित रिवीजन प्रार्थना पत्रों पर 26 मई से सुनवाई शुरू कर देंगे। वहीं अब रिवीजन कमेटी बनाने के लिए छह सप्ताह का समय मांग रहे हैं। ऐसे में विभाग ने गलत शपथ पत्र दिया है। इस पर अदालत ने शिक्षा विभाग को कहा कि ऐसा शपथ पत्र क्यों दिया है। यह अवमानना है और क्यों ना इसके लिए दोषी अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा विभाग को आखिरी मौका देते हुए तीन सप्ताह में रिवीजन कमेटी बनाने का आदेश दिया है। दरअसल भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की याचिका पर हाईकोर्ट ने 9 सालों से रिवीजन कमेटी नहीं बनाए जाने पर शिक्षा सचिव को वीसी या व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। वहीं गत सुनवाई पर शिक्षा विभाग ने कहा था कि कमेटी में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त नहीं हुए हैं और लंबित रिवीजन प्रार्थना पत्रों की संख्या को देखते हुए 26 मई से कमेटी सुनवाई करेगी।

नगरीय निकायों के पुर्नगठन एवं पुर्नसीमांकन के प्रस्तावों को लेकर बैठक

जयपुर। मंत्रिमण्डल सचिवालय, राजस्थान सरकार के आदेशों की अनुपालना में मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में राज्य में नगरीय निकायों के पुर्नगठन एवं पुर्नसीमांकन के प्राप्त प्रस्तावों को लेकर परीक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्रीमण्डलीय उप समिति के सदस्य राज्यमंत्री वन विभाग संजय शर्मा, राज्यमंत्री सहकारिता विभाग गौतम कुमार तथा समिति के संयोजक राज्यमंत्री नगरीय विकास विभाग झाबर सिंह खर्रा द्वारा इस बैठक में अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग की नगरीय निकायों के पुर्नगठन एवं पुर्नसीमांकन के प्रस्तावों पर समीक्षा एवं गहन चर्चा की गई।

करोना की आशंका : चिकित्सा मंत्री ने बुलाई आपात बैठक

■ वैरियंट घातक नहीं, फिर भी सतर्क रहें : खींवसर

जयपुर। देशभर में कोविड-19 के नए मामले सामने आने के बाद राजस्थान सरकार सतर्क मोड में आ गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सोमवार को चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक आयोजित कर संक्रमण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अनुसार वर्तमान में सामने आया कोविड वैरियंट घातक नहीं है, लेकिन खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण दिखने पर नागरिकों को तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। उन्होंने संवेदनशील वर्ग जैसे बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर रोगियों व बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी।

चिकित्सा मंत्री खींवसर ने अधिकारियों से कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने भले ही स्थिति को गंभीर नहीं बताया हो, फिर भी अस्पतालों में जांच, दवाएं और उपचार की व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त रखी जाए। आईएलआई के लक्षण दिखने पर किसी भी मरीज को आवश्यक जांच और चिकित्सा तुरंत उपलब्ध होनी चाहिए। बैठक के दौरान चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स की कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो प्लांट बंद हैं, उन्हें शीघ्र मरम्मत कर चालू कराया जाए। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड को लेकर जारी दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से की जाए।

सरकार ने आमजन से अपील की है कि घबराएं नहीं, लेकिन एहतियात जरूर बरतें। लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट करें, चिकित्सक से संपर्क करें और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचें।

गली-गली में भाजपा की तिरंगा यात्रा

जयपुर। भाजपा की ओर से भारतीय सेना के शौर्य को नमन करने के लिए निकाली जा रही तिरंगा यात्रा की गूंज जयपुर शहर की गलियों में भी सुनाई दी। भाजपा से वार्ड 71 से पार्षद मुकेश काका के नेतृत्व में मंगलवार को पत्रकार कॉलोनी रोड पर आनंद गार्डन गोल्यवास से विभिन्न मार्गों से होते हुए निमड़ी बालाजी तक निकाली गई। डीजे की धुन पर देशभक्ति गीतों की गूंज के बीच निकली इस तिरंगा यात्रा में वार्ड 67 से पार्षद गणेश जाट, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र खरवास, महामंत्री राजकुमार, वार्ड अध्यक्ष मानसिंह नरूका, समाजसेवी नरेंद्र हर्ष, गोपाल भींवाल, इस्पेक के प्यारेलाल शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, गिरिराज शर्मा, शंकर शर्मा, मोहन शर्मा, बनवारी शर्मा आदि शामिल थे।

सीतापुरा से टोडी मोड़ तक प्रस्तावित मेट्रो परियोजना को लेकर बैठक

जयपुर। बजट घोषणा में शामिल सीतापुरा से टोडी मोड़ तक प्रस्तावित मेट्रो परियोजना को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्य की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की।

इस बैठक में परियोजना की संभावनाओं, आवश्यकताओं और व्यवहार्यता पर विस्तार से चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को जनता के हित में शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाए और सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं पर समुचित कार्ययोजना तैयार की जाए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया, एनएचएआई के आरओ प्रदीप, जयपुर मेट्रो के डायरेक्टर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह मेट्रो परियोजना जयपुर शहर के यातायात को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सकेगी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की अध्यक्षता में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।

तिंरगा यात्रा का गलत फीडबैक देने पर कहा-सुनी

जयपुर। प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा की ओर से तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर प्रदेश पर सभी जगह तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। जयपुर देहात दक्षिण जिले की तिरंगा यात्रा को लेकर प्रदेश के पदाधिकारी को गलत फीडबैक देने के मामले में जयपुर देहात दक्षिण जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर व तिरंगा यात्रा के प्रभारी भूपेंद्र सैनी के बीच भाजपा कार्यालय में जमकर कहा सुनी हुई। दोनों नेताओं के बीच भाजपा कार्यालय में हुई। इस दौरान भाजपा पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से सैनी के द्वारा जयपुर देहात दक्षिण का गलत फीडबैक भाजपा प्रदेश नेताओ को देने के मामले में ये कहा सुनी हुई।